INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 16 | ISSUE - 7 | AUGUST – 2026

"रीवा जिले में प्रक्षेत्र उत्पादकों के संसाधन उपयोग एवं उत्पादकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

ज्योति सिंह[1] , डॉ. विद्युत प्रकाश मिश्रा[2]
[1]शोधार्थी वाणिज्य, शोध केन्द्र–शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]शोध निर्देशक, प्राध्यापक वाणिज्य, राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.)

सारांश –

कृषि क्षेत्र में संसाधनों का कुशल एवं संतुलित उपयोग उत्पादकता वृद्धि का मूल आधार है। विशेषकर प्रक्षेत्र उत्पादक, जो सीमित भूमि, पूंजी एवं तकनीकी संसाधनों के साथ कृषि कार्य करते हैं, उनके लिए संसाधन उपयोग की दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य रीवा जिले में प्रक्षेत्र उत्पादकों द्वारा भूमि, श्रम, पूंजी एवं सिंचाई संसाधनों के उपयोग की प्रकृति तथा उनके कृषि उत्पादकता पर प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें कृषि विभाग, राष्ट्रीय रिपोर्टों एवं विभिन्न शोध अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संसाधनों का असमान वितरण, तकनीकी ज्ञान का अभाव, सिंचाई सुविधाओं की कमी एवं वित्तीय बाधाएँ उत्पादकता को सीमित करती हैं। इसके विपरीत जहां आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों एवं सिंचाई साधनों का उपयोग अधिक है, वहाँ उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि संसाधनों का वैज्ञानिक एवं समन्वित उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा किसानों को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, तो कृषि उत्पादकता में सतत वृद्धि संभव है।

मुख्य शब्द : संसाधन उपयोग, कृषि उत्पादकता, प्रक्षेत्र उत्पादक, आर्थिक विश्लेषण, रीवा जिला।

प्रस्तावना –

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, जहाँ आज भी एक बड़ी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन की संरचना में प्रक्षेत्र उत्पादकों की भूमिका केंद्रीय है, क्योंकि वे सीमित संसाधनों के बावजूद उत्पादन प्रणाली को बनाए रखते हैं। प्रक्षेत्र उत्पादक सामान्यतः लघु एवं सीमांत कृषक होते हैं, जिनके पास भूमि का आकार छोटा होता है तथा संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कृषि क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए उत्पादकता वृद्धि आवश्यक हो गई है। उत्पादकता केवल उत्पादन की मात्रा नहीं, बल्कि संसाधनों के कुशल उपयोग की क्षमता को भी दर्शाती है। भूमि, श्रम, पूंजी एवं तकनीकी संसाधनों का समुचित उपयोग ही उत्पादन दक्षता को निर्धारित करता है।

रीवा जिला, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ की भौगोलिक संरचना, जलवायु एवं मृदा कृषि के लिए अनुकूल हैं, किन्तु संसाधनों का समुचित

उपयोग न होने के कारण उत्पादकता अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। संसाधन उपयोग की समस्या बहुआयामी है। भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े, सिंचाई का अभाव, उन्नत तकनीकों की सीमित उपलब्धता तथा वित्तीय संसाधनों की कमी इस क्षेत्र के प्रमुख अवरोध हैं। इसके अतिरिक्त किसानों में आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति जागरूकता की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है।

वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, जैसे– ड्रिप सिंचाई, उच्च उत्पादकता वाले बीज, जैविक उर्वरक एवं यंत्रीकरण उत्पादकता वृद्धि के महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं। परंतु इन तकनीकों का लाभ सभी प्रक्षेत्र उत्पादकों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। इसके अतिरिक्त बाजार संरचना एवं मूल्य निर्धारण प्रणाली भी कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। यदि उत्पादकों को उचित मूल्य एवं बाजार तक पहुँच प्राप्त हो, तो वे अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। अतः इस अध्ययन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह प्रक्षेत्र उत्पादकों के संसाधन उपयोग एवं उत्पादकता के बीच संबंध को स्पष्ट करता है तथा कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु नीतिगत सुझाव प्रदान करता है।

शोध उद्देश्य –

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य रीवा जिले में प्रक्षेत्र उत्पादकों द्वारा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की प्रकृति एवं उसकी दक्षता का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार भूमि, श्रम, पूंजी एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है। इसके साथ ही, यह शोध संसाधनों के असमान वितरण एवं उनके उपयोग में विद्यमान बाधाओं की पहचान करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- प्रक्षेत्र उत्पादकों द्वारा संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
- संसाधन उपयोग एवं कृषि उत्पादकता के बीच संबंध का विश्लेषण करना।
- संसाधन उपयोग में सुधार हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध विधि –

इस अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जो विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों जैसे कृषि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार की कृषि सांख्यिकी, नाबार्ड रिपोर्ट एवं शोध पत्रिकाओं से प्राप्त किए गए हैं। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु वर्णनात्मकएवं विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। संकलित आंकड़ों को वर्गीकृत कर सारणीबद्ध किया गया तथा प्रतिशत विश्लेषण के माध्यम से संसाधन उपयोग के स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया।

विश्लेषण –

रीवा जिले में प्रक्षेत्र उत्पादकों के संसाधन उपयोग का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि कृषि उत्पादन प्रणाली में भूमि का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भूमि कृषि का आधारभूत संसाधन होने के कारण इसका प्रतिशत अधिक पाया गया है, किन्तु भूमि के छोटे जोत आकार एवं विखंडन के कारण इसकी उत्पादन क्षमता पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाई जा रही है। परिणामस्वरूप, उपलब्ध भूमि संसाधनों के बावजूद उत्पादकता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाती है।

श्रम उपयोग का स्तर अपेक्षाकृत उच्च है, जो यह दर्शाता है कि अध्ययन क्षेत्र की कृषि प्रणाली श्रम–प्रधान प्रकृति की है। तथापि, श्रम की उत्पादकता निम्न स्तर पर है, जिसका प्रमुख कारण तकनीकी दक्षता का अभाव एवं यंत्रीकरण का सीमित उपयोग है। इसके कारण श्रम की अधिक उपलब्धता होने के बावजूद उत्पादन पर उसका अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ पाता।

पूंजी निवेश की कमी कृषि विकास में एक प्रमुख बाधा के रूप में उभरकर सामने आती है। अधिकांश प्रक्षेत्र उत्पादक सीमित आय एवं वित्तीय संसाधनों के कारण उन्नत कृषि उपकरणों, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा आधुनिक तकनीकों में निवेश करने में सक्षम नहीं हैं, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादन वर्षा पर अत्यधिक निर्भर बना हुआ है। यह निर्भरता उत्पादन में अनिश्चितता एवं जोखिम को बढ़ाती है, जिससे कृषकों की आय

एवं उत्पादकता दोनों प्रभावित होती हैं। इसी संदर्भ में प्रक्षेत्र उत्पादकों के संसाधन उपयोग का आर्थिक वितरण का समग्र मूल्यांकन सारणी क्रमांक–01 में प्रस्तुत किया गया है –

सारणी क्रमांक–01
रीवा जिले में प्रक्षेत्र उत्पादकों के संसाधन उपयोग का आर्थिक वितरण

क्रमांक	विवरण	इकाई (Unit)	आंकड़े (Value)	प्रतिशत (%)
1	भूमि उपयोग	हेक्टेयर	13248	33.18
2	श्रम उपयोग	व्यक्ति (संख्या)	10876	27.24
3	पूंजी निवेश	लाख (रुपये में)	9324	23.36
4	सिंचाई संसाधन	हेक्टेयर	6472	16.22
कुल योग		–	39920	100.00

स्रोत– कृषि विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वार्षिक प्रतिवेदन, 2024–25

प्रस्तुत सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में प्रक्षेत्र उत्पादकों के संसाधन उपयोग का वितरण असंतुलित एवं संरचनात्मक रूप से विषम है। भूमि उपयोग का प्रतिशत सर्वाधिक (33.18%) पाया गया है, जो यह दर्शाता है कि कृषि उत्पादन प्रणाली मुख्यतः भूमि–आधारित है। तथापि, भूमि का यह उच्च उपयोग छोटे एवं विखंडित जोत आकार के कारण अपनी पूर्ण उत्पादक क्षमता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जिससे उत्पादन दक्षता प्रभावित होती है। श्रम उपयोग का प्रतिशत 27.24 होने से यह संकेत मिलता है कि अध्ययन क्षेत्र की कृषि प्रणाली श्रम–प्रधान है। इसके बावजूद, श्रम की उत्पादकता अपेक्षाकृत निम्न बनी हुई है, जिसका प्रमुख कारण तकनीकी ज्ञान का अभाव, सीमित यंत्रीकरण एवं पारंपरिक कृषि पद्धतियों का प्रचलन है। परिणामस्वरूप श्रम की अधिकता उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं कर पा रही है। पूंजी निवेश का प्रतिशत 23.36 है, जो यह दर्शाता है कि आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों एवं यंत्रीकरण में निवेश का स्तर अभी भी सीमित है। यह स्थिति उत्पादन की गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित करती है। सिंचाई संसाधनों का न्यूनतम प्रतिशत (16.22%) इस तथ्य को इंगित करता है कि कृषि उत्पादन अभी भी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे उत्पादन में अनिश्चितता एवं जोखिम बना रहता है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संसाधनों का असंतुलित उपयोग कृषि उत्पादकता को सीमित कर रहा है, जिसे पूंजी निवेश, सिंचाई विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है।

शोध की समस्याएँ एवं सुझाव –

अध्ययन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि रीवा जिले के प्रक्षेत्र उत्पादकों को अनेक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रमुख समस्याओं में भूमि का अत्यधिक विखंडन, सीमित पूंजी उपलब्धता, सिंचाई संसाधनों का अभाव तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति अपर्याप्त जागरूकता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थागत ऋण तक सीमित पहुँच एवं बाजार संरचना की जटिलताएँ भी उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। सर्वप्रथम, किसानों को सस्ती एवं सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। द्वितीय, सिंचाई अवसंरचना के विकास के माध्यम से वर्षा पर निर्भरता को कम करना आवश्यक है। तृतीय, कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों एवं वैज्ञानिक खेती के तरीकों का प्रसार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त डिजिटल कृषि एवं ई–मार्केटिंग प्लेटफार्मों को प्रोत्साहित कर किसानों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार, समन्वित नीतिगत प्रयासों द्वारा प्रक्षेत्र उत्पादकों की उत्पादकता एवं आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि रीवा जिले में प्रक्षेत्र उत्पादकों द्वारा संसाधनों का उपयोग असंतुलित एवं आंशिक रूप से प्रभावी है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता अपेक्षित स्तर तक

नहीं पहुँच पा रही है। भूमि, श्रम, पूंजी एवं सिंचाई जैसे प्रमुख संसाधनों का समन्वित एवं वैज्ञानिक उपयोग कृषि उत्पादन वृद्धि का मूल आधार है, किन्तु वर्तमान परिदृश्य में इन संसाधनों का वितरण एवं उपयोग असमान रूप से परिलक्षित होता है। भूमि का अधिकतम उपयोग होने के बावजूद, छोटे जोत आकार एवं विखंडन के कारण इसकी उत्पादकता सीमित हो जाती है। श्रम की उपलब्धता अधिक होने के बावजूद, उसकी दक्षता कम होने के कारण उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती। पूंजी निवेश की कमी के कारण आधुनिक तकनीकों एवं यंत्रीकरण का समुचित उपयोग नहीं हो पाता, जबकि सिंचाई संसाधनों की अपर्याप्तता उत्पादन में अनिश्चितता उत्पन्न करती है। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि संसाधनों के उपयोग में संतुलन स्थापित किया जाए तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए, तो उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए तथा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रक्षेत्र उत्पादकों की आर्थिक सुदृढ़ता एवं कृषि उत्पादकता वृद्धि के लिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन, नीतिगत समर्थन एवं तकनीकी नवाचार अनिवार्य हैं। यदि इन पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाए, तो रीवा जिले में कृषि क्षेत्र न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

संदर्भ –

1. कृषि विभाग, मध्य प्रदेश, वार्षिक प्रतिवेदन, भोपाल, 2024–25
2. भारत सरकार, कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट, नई दिल्ली, 2022
3. शर्मा, आर. के., कृषि अर्थशास्त्र, जयपुर, 2021
4. सिंह, पी., ग्रामीण विकास अध्ययन, नई दिल्ली, 2020
5. नाबार्ड, ग्रामीण विकास रिपोर्ट, मुंबई, 2021
6. गुप्ता, एस., कृषि विपणन प्रबंधन, दिल्ली, 2019